लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 295

जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवंबर, 2024 को दिया जाएगा

मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र

295. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल्य निगरानी प्रभाग के अंतर्गत मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों (पीआरसी) के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या ये उद्देश्य लक्ष्यों के अनुसार प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारत में मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में से एक भी मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्र नहीं है

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा अंतिम बार पीआरसी का सर्वेक्षण और विस्तार किस तिथि को किया गया था?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (छ): उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी प्रभाग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों में स्थित मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों (पीआरसी) द्वारा रिपोर्ट की गई चयनित खाद्य वस्तुओं की दैनिक उपभोक्ता खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी करता है। पीआरसी का उद्देश्य डेटा के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए मूल्य निगरानी प्रभाग को दैनिक कीमतों की रिपोर्ट करना है। बफर से स्टॉक जारी करने, निर्यात-आयात नीति आदि के लिए उचित निर्णय लेने के लिए कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का विधिवत विश्लेषण किया जाता है।

आज की तिथि तक, 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 555 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र स्थापित नहीं किया है। कीमतों के आंकड़ों की प्रतिनिधित्व क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने 2022-23 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया था कि वे जहां भी संभव हो, जिलों में मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र स्थापित करें। परिणामस्वरूप, मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या दिसंबर, 2021 में 178 से बढ़कर नवंबर, 2024 में 555 हो गई है।

****